नवभारत
ग्वालियर, मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026

बालिका शौचालय के निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करें–डीएम

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 27 अप्रैल. कलेक्टर शीला दाहिमा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक के दौरान निर्देश दिये कि राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत स्कूलों में बनाये जा रहे बालिका शौचालयों के निर्माण का कार्य शीघ्रता के साथ पूर्ण किया जायें, उन्होंने डीपीसी को निर्देश दिये कि कार्य की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायें तथा शौचालय निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखा जायें। इसके साथ ही उन्होंने निक्षय मित्र बनाये जाने और ग्रामीण क्षेत्रो में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जायें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा, कराहल बीएस श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। निर्देश दिये कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय कर ग्रामीण क्षेत्रो में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करें, इसके लिए कैलेण्डर तैयार किया जाये तथा निर्धारित तिथियों में शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जायें, उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान गर्भवती महिलाओं की जांच सुनिश्चित की जायें।

शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं के एएनसी पंजीकरण अनमोल पोर्टल पर किये जायें। रक्त की कमी वाली गर्भवती महिला को एफसीएम एवं आयरन सुक्रोज दिया जायें और प्रसवपूर्व नियमित रूप से जांच की जायें। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम की जिला स्तर से मॉनीटरिंग की जाये तथा क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत टीबी मरीजों को निक्षय अभियान के तहत फूड बॉस्केट वितरित की जायें, इसके लिए अधिक से अधिक निक्षय मित्र बनाये जाये और उनसे सहयोग प्राप्त किया जायें। उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के बुजुर्गो के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के निर्देश भी दिये। कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत संचालित कार्यो की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि जल संरक्षण से संबंधित कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराये जायें तथा उपयोगी संरचनाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया जायें। उन्होंने कहा कि शासकीय भवनों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कार्य 7 दिवस में पूर्ण कराये जायें। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जायें और प्रगणकों को सामग्री का वितरण सुनिश्चित किया जायें। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में तकनीकी एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तर पर कन्ट्रोलरूम भी स्थापित किया गया है।

सहकारी संस्थाओं में लक्ष्यानुरूप बनाये जायें नवीन सदस्य

श्योपुर.मप्र शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्यान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में बहुउद्देशिय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में नवीन सदस्य बनाये जाने जा रहे है। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि श्योपुर जिले भी लक्ष्य अनुरूप 6 हजार 748 नवीन सदस्य बनाये जायें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जारी गेहूं उपार्जन कार्य के दौरान ऐसे कृषको को भी सदस्य बनाया जा सकता है, जो समर्थन मूल्य पर गेहूं का विक्रय करने आ रहे है तथा पूर्व से किसी सोसायटी से सदस्य के रूप में नही जुडे है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में डॉ भीमराव अम्बेडकर जंयती अवसर पर सदस्यता वृद्धि के लिए अभियान की शुरूआत की गई है। यह अभियान 15 मई तक जारी रहेगा। इसके तहत श्योपुर जिले की 47 संस्थाओं में 6 हजार 748 नवीन सदस्यों को जोडने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में पूर्व में 67 हजार 600 सदस्य संस्थाओं में पंजीकृत है। सहकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सहकारी संस्थाओं में नवीन सदस्यता के लिए 100 रूपये प्रवेश शुल्क तथा 500 रूपये अंशदान राशि निर्धारित की गई है। इस प्रकार 600 रूपये की राशि जमा कर नवीन सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। नवीन सदस्यता के लिए आधारकार्ड, पासपोर्ट फोटो, समग्र आईडी आदि दस्तावेजो के साथ नजदीकी सहकारी बैंक शाखा, पैक्स संस्थाओं आदि पर जाकर पंजीयन कराया जा सकता है। सहकारी समिति से जुडे सदस्यों को शासन द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही खाद एवं बीज की सुविधा, फसल बीमा की सुविधा आदि सुविधाएं प्राप्त होती है।

ज्ञान भारतम् समिति का गठन

नवभारत न्यूज
श्योपुर 27 अप्रैल. पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्राहलय मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा भारत की हस्तलिखित विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण एवं प्रचार–प्रसार हेतु दिये गये निर्देशो के क्रम में कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा की अध्यक्षता में ज्ञान भारतम् जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद रूपेश उपाध्याय समिति में सदस्य–सचिव होंगे। इसके साथ ही सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद, प्राचार्य शासकीय पीजी कॉलेज श्योपुर डॉ ओपी शर्मा, सहायक प्राध्यापक खेमराज आर्य एवं अनिल तोमर को सदस्य बनाया गया है। एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा समन्यक रहेंगे। समिति द्वारा जिले में स्थित निजी शोध संस्थान, महाविद्यालयों, ग्रंथालय, मंदिरों, मठ–आश्रम, प्रायवेट ट्रस्ट इत्यादि में संरक्षित प्राचीन हस्तलिखित पाडू लिपियों की खोजकर ज्ञान भारतम् एप पर अपलोड किया जाना है।

गौ भक्तों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

विजयपुर नगर के गौ भक्तो ने आज एसडीएम अभिषेक मिश्र को गोमाताओ के संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन देकर गौ माताऔ पर हो रहे अत्याचार ब गौ माता की हो रही दुर्दशा पर गहरा खेद प्रकट किया, तथा गौ माता सबसे पहिले पायदान पर है गौ माता मैं तेतीस करोड़ देवताओं का बास है पर आज के युग में इन्सान गाय माता को भूलगया है। इसलिये प्रधानमंत्री मोदी जी से विजयपुर नगर के गौ सेबकौ की ओर से निबेदन है कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाबे।

गंगा दशहरा पर 10 हजार ग्रामों में निकलेंगी कलश यात्राएं

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 27 अप्रैल. मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, वैशाली नगर, भोपाल में दो दिवसीय राज्य स्तरीय सी.एम. सोशल इंटर्न प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना तथा उन्हें समाज के उत्थान के लिए तैयार करना है।

उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आगामी 25 मई, गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश की लगभग 10 हजार पंचायतों में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत भव्य 'जल गंगा कलश यात्राएं' आयोजित की जाएंगी। इसके तहत गांवों की प्राचीन जल संरचनाओं जैसे बावड़ी, कुएं, सरोवर और तालाबों की साफ-सफाई कर उनका पूजन किया जाएगा और वहां से कलश यात्राएं निकाली जाएंगी।

श्री नागर ने कहा कि इस अभियान में परिषद की नवांकुर सखियों के नेटवर्क के साथ ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने प्रदेशभर से आए युवाओं से इस जन अभियान से जुड़कर जल संरक्षण के इस महत्वपूर्ण प्रयास को सफल बनाने का आह्वान किया

रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री शीला दाहिमा द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के लिए रजिस्ट्रीकरण तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किये गये है। जारी आदेश के अनुसार जनपद पंचायत श्योपुर, कराहल एवं विजयपुर क्षेत्र के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा तहसीलदारों को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अपर कलेक्टर को संपूर्ण जिले के लिए अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार नगरपालिका परिषद श्योपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार श्योपुर को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपरिषद विजयपुर के लिए तहसीलदार विजयपुर को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं नायब तहसीलदार विजयपुर को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा नगरपरिषद बडौदा के लिए तहसीलदार बडौदा को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बडौदा को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया है। नगरपालिका परिषद श्योपुर के लिए अपर कलेक्टर तथा नगरपरिषद विजयपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर एवं नगरपरिषद बडौदा के लिए अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर अपीलीय अधिकारी रहेगे।

जिला प्रशासन ने की नरवाई न जलाने की अपील

नवभारत न्यूज
श्योपुर 27 अप्रैल. जिले में गेहूं फसल की कटाई लगभग पूर्ण हो गई है, जिला प्रशासन ने किसान भाईयों से अपील की है कि नरवाई में आग न लगाए बल्कि उसका प्रबंधन कर अतिरिक्त आय प्राप्त करें। नरवाइ प्रबंधन के लिए जिले में 25 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये गये है, जो अपने–अपने क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में ग्रामीणों को नरवाई न जलाने के लिए प्रेरित करेंगे।

कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा जारी की गई अपील में उप संचालक कृषि जीके पचौरिया ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से एक टन गेहूं के भूसे में लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम, 1.2 किलोग्राम सल्फर, गेहूं द्वारा अवशोषित 50–70 प्रतिशत सूक्ष्म पोषक तत्व और 400 किलोग्राम कार्बन होता है, जो जलाने से नष्ट हो जाता है। मिट्टी का तापमान 150 से 170 सेंटीग्रेड तक बढ जाता है। इसके अलावा मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म एवं लाभदायक जीवाणु जलकर नष्ट हो जाते है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है एवं फसलों के लिए मिट्टी में आवश्ययक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है एवं मिट्टी धीर–धीरे बंजर हो जाती हे जिसमें आवश्यक पोषक तत्वों का उपयोग करने पर भी फसलों का उत्पादन नही लिया जा सकता है। पोषक तत्वों के नुकसान के अलावा, मिट्टी के कुछ गुण जैसे मिट्टी का तापमान, पीएच, नमी, उपलब्ध फास्फोरस और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ भी नरवाई को जलाने से प्रभावित होते है। अनुमान है कि एक टन गेहूं की नरवाई जलाने से 11 किलोग्राम , 58 किलोग्राम कार्बन मोनो ऑक्साइड, 1400 किलोग्राम कार्बन डाईऑक्साइड, 199 किलोग्राम राख और 1.2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, उत्सर्जित होती है। ये गैसें वायु की गुणवत्ता में गिरावट लाती है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, जैसे नेत्र और त्वचा रोगों में वृद्धि, सूक्ष्म कण दीर्घकालिक हृदय और फेफड़ो के रोगो को बढाने के कारक है।

फसल अवशेषों का प्रबंधन करने से मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाना, फसल की उत्पादकता बढाना, उत्पादन लागत कम कर कृषकों की आय को बढ़ाना, फसल अवशेषों का समुचित सही उपयोग कर कृषकों की अतिरिक्त आय के विकल्प उपलब्ध कराना, फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को कम कर वायु प्रदूषण कम करना।

उन्होंने किसान भाईयों से अपील की है कि गेहूं की नरवाई में आग नही लगाये, बल्कि स्ट्रॉ रीपर से भूसा बनाकर 2000 रूपये प्रति ट्रॉली की आय प्राप्त कर सकते है। इस भूसे को गौशालाओं एवं पशुपालकों को विक्रय कर सकते है। जिन किसान भाईयों द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग एवं अन्य फसलें लगाई जा रही है, वह सुपर सीडर एवं अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई कर सकते है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूयनल के निर्देशानुसार किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर पर्यावरण मुआवजा अदा करना होगा। 02 एकड या उससे कम भूमि धारक 2500 रूपये प्रति घटना। 02 एकड से अधिक लेकिन 05 एकड से कम भूमि धारक 5000 रूपये प्रति घटना। 05 एकड से अधिक भूमि धारक 15000 रूपये प्रति घटना होगा।

कृषि आदान व्यापारियों का देशव्यापी विरोध : सौंपा ज्ञापन ,कृषि व्यवस्था पर मंडराया संकट

जबरन लिंकिंग, कम मार्जिन और सख्त कानूनों के विरोध में भड़के व्यापारी, समाधान नहीं तो अनिश्चितकालीन बंद

नवभारत न्यूज
विजयपुर 27 अप्रैल. कृषि आदान विक्रेता संघ जिला श्योपुर के बैनर तले सोमवार को विजयपुर में खाद, बीज और कीटनाशक व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। देशव्यापी आह्वान के तहत व्यापारियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करते हुए एसडीएम विजयपुर अभिषेक मिश्रा एवं कृषि विस्तार अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता एवं सचिव हकीमुद्दीन दाऊदी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि देशभर के करीब 5 लाख व्यापारी पिछले 10 वर्षों से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे व्यापारी वर्ग में गहरा असंतोष व्याप्त है। व्यापारियों ने सबसे बड़ी समस्या उर्वरक कंपनियों द्वारा सब्सिडी वाले खाद के साथ गैर–जरूरी उत्पादों की जबरन बिक्री को बताया। उन्होंने इसे अपराध घोषित करने और पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही खाद की डिलीवरी रेल हेड पर दिए जाने से प्रति बैग 40 से 50 रुपए अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। ज्ञापन में उर्वरकों पर डीलर मार्जिन कम से कम करने पोर्टल को ग्रामीण विक्रेताओं के लिए वैकल्पिक बनाने तथा नए बीज अधिनियम एवं कीटनाशक विधेयक 2025 में रिटेल डीलरों पर लगाए गए सख्त प्रावधानों को शिथिल करने की मांग की गई। इसके अलावा व्यापारियों ने यह भी कहा कि सीलबंद पैकिंग में नमूना फेल होने पर विक्रेता को दोषी न ठहराया जाए, बल्कि केवल गवाह माना जाए क्योंकि उत्पाद की गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की होती है।

व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कई बार किसानों द्वारा झूठी शिकायतें कर व्यापारियों को ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसी स्थिति में जिला स्तर पर जांच कमेटी बनाकर ही कार्रवाई की जाए। साथ ही लाइसेंस निलंबन की स्थिति में 21 दिन के भीतर स्वत: बहाली का प्रावधान करने की भी मांग की गई। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि एक माह के भीतर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए तो व्यापारी मजबूरी में अनिश्चितकालीन बंद करने को बाध्य होंगे। इससे कृषि उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा और किसानों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कृषि आदान व्यापारी मौजूद रहे और प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की।

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठक

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 27 अप्रैल. 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कपिल मेहता की अध्यक्षता में जिला स्थापना में पदस्थ न्यायाधीशगण के साथ बैठक का आयोजन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में किया गया। बैठक में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित न्यायाधीशगण को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा के माध्यम से निराकरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदाय किये गये। इसी कम में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्युत विभाग के अधिकारीगण व संबंधित अधिवक्तागण एवं बीमा क्लेम से संबधित अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन जिला न्यायालय श्योपुर परिसर में स्थित एडीआर भवन में किया गया।

उक्त बैठक में नेशनल लोक अदालत में विद्युत व बीमा क्लेम के प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदाय किये एवं उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल कियान्वयन हेतु अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार हेतु निर्देशित किया। बैठक में माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत, माननीय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश माननीय तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महोदय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विद्युत विभाग के अधिकारी व संबंधित अधिवक्तागण व बीमा क्लेम संबंधी अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

भोपाल रुबात मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग

भोपाल, 26 अप्रैल. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से हज यात्रियों को रुबात सुविधा नहीं मिलने के मुद्दे पर मध्यप्रदेश सर्वधर्म सद्भावना मंच के सचिव हाजी मोहम्मद इमरान हारून ने भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस मसले के समाधान के लिए बड़े स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के उच्च पदाधिकारियों को ज्ञापन भेजा जाएगा.

एमपी ई–सेवा पोर्टल एवं मोबाइल एप नागरिक सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल मंच

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 27 अप्रैल.मध्य प्रदेश शासन द्वारा नागरिकों को सरल, पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एमपी ई–सेवा पोर्टल एवं मोबाइल एप की सुविधा प्रदान की गई है। यह शासन की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों की समस्त नागरिक–केंद्रित सेवाएं अब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

ई–सेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसमें सुविधा सेवाएं, प्रमाणपत्र, लाइसेंस एवं कर, राजस्व, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पेंशन एवं लाभ, सामाजिक कल्याण एवं सशक्तिकरण, शिक्षा, शहरीकरण, आवास एवं पर्यावरण, ऊर्जा, परिवहन, व्यवसाय, निवेश, स्वास्थ्य, न्याय एवं शिकायत, पर्यटन, युवा एवं खेल, रोजगार, उद्यमिता एवं कौशल से संबंधित सेवाएं सम्मिलित हैं। पोर्टल की प्रमुख सुविधाओं में शासकीय योजनाओं की पात्रता जांच, ऑनलाइन आवेदन, रीयल–टाइम आवेदन ट्रैकिंग, डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड, समग्र इंटीग्रेशन, समग्र प्रोफाइल के आधार पर पूर्व–भरा हुआ आवेदन फॉर्म, सिंगल साइन–ऑन (एसएसओ) तथा इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण हेल्पलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। एमपी ई–सेवा पोर्टल पर तथा एंड्रॉइड एवं आईओएस मोबाइल एप के रूप में उपलब्ध है। नागरिकों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में इस डिजिटल सुविधा का उपयोग कर शासकीय सेवाओं का लाभ उठाएं। एमपी ई–सेवा पोर्टल पर 50 से अधिक विभागों की 1700 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध है, जिनका लाभ घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। एमपी ई–सेवा पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का उपयोग कर डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकते है।

54 जिलों के 365 केंद्रों पर संपन्न हुई एमपीपीएससी प्रीलिम्स

भोपाल, 26 अप्रैल. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को पूरे प्रदेश आयोजित की गई. जो कि प्रदेश भर के 54 जिलों के 365 केंद्रों पर संपन्न करा दी गई. परीक्षा निर्विघ्न रूप से संपन्न होने की सूचनाएं हैं.बता दें पहली बार परीक्षा में सुरक्षा प्रणाली को कड़ा बनाने के लिये थ्री–लेयर सिक्योरिटी लागू की गई थी. जिसमें एडमिट कार्ड स्कैनिंग, मेटल डिटेक्टर और बायोमेट्रिक जांच भी शामिल रही.

पीएम राहत योजना में डेढ लाख तक के कैशलेस उपचार की सुविधा

नवभारत न्यूज
श्योपुर 27 अप्रैल. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार) योजना सम्पूर्ण भारत में लागू कर दी गई है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को डेढ़ लाख तक मुफ्त ईलाज सरकारी एवं चिन्हित प्रायवेट अस्पतालों में मिलेगा।

भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गई है। यदि दुर्घटना पीड़ितों को पहले एक घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, तो लगभग 50 प्रतिशत मौतों को टाला जा सकता है। सड़क दुर्घटना पीड़ित, राह–वीर या दुर्घटना स्थल पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति 112 डायल करके निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकता है और एम्बुलेंस सहायता लें सकता है। ''पीएम राहत योजना'' अन्तर्गत किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों की अवधि तक प्रति व्यक्ति 01 लाख 50 हजार रूपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। जीवन को खतरे में नहीं डालने वाले मामलों में अधिकतम 24 घंटे तक तथा जीवन के लिये घातक मामलों में अधिकतम 48 घंटे तक स्टेबलाईजेशन उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा एकीकृत डिजीटल प्रणाली पर पुलिस प्रमाणीकरण के अधीन होगी। ''पीएम राहत योजना'' किसी भी दुर्घटना पीड़ित का वित्तीय अड़चनों के कारण जीवनरक्षक उपचार से वंचित न रहना सुनिश्चित करते हुए सड़क दुर्घटना में पीड़ितों का जीवन बचाने तथा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज

भोपाल, 26 अप्रैल. संसदीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण और संसदीय व विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के मुद्दे पर केंद्रित मध्यप्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को आयोजित किया गया है.

सत्र की तैयारियों को रविवार को अंतिम स्वरूप दे दिया गया. सोमवार को सदन में मुख्यमंत्री एवं सदन के नेता डॉ मोहन यादव एक शासकीय संकल्प पेश करेंगे, जिसके माध्यम से महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर लागू करने का अनुरोध किया जाएगा. इस शासकीय संकल्प पर दिनभर चर्चा होगी और इसके लिए सत्तारूढ़ दल भाजपा के साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने तैयारियां की हैं. भाजपा की ओर से इस संकल्प पर चर्चा के लिए महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की रणनीति अपनाने की बात सामने आई है.

सीमावर्ती क्षेत्रों में सख्त निगरानी बढ़ाएं : एसपी

नशे के खिलाफ प्रभावी मुहीम चलाएं- डीएम

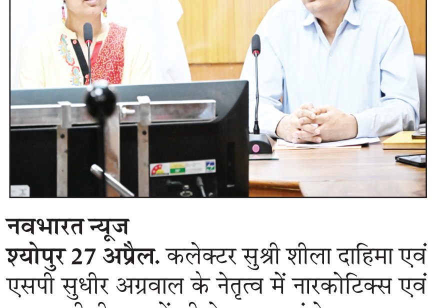

नवभारत न्यूज
श्योपुर 27 अप्रैल. कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा एवं एसपी सुधीर अग्रवाल के नेतृत्व में नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय (छब्व्त्क) के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में एडीएम रुपेश उपाध्याय, एसडीएम गगन सिंह मीणा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर जिले में नशे के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण एवं समन्वित कार्यवाही की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने सीमावर्ती राज्यों से लगे क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, नियमित चेकिंग के लिए विस्तृत शेड्यूल तैयार करने तथा अवैध मादक फसलों की खेती पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और अंतर–विभागीय समन्वय को और मजबूत किया जाए।

कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूल एवं कॉलेजों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाए। साथ ही मादक पदार्थों के सेवन एवं एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर को मेडिकल स्टोर्स के नियमित भ्रमण एवं निगरानी के निर्देश दिए।

कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा एवं एसपी सुधीर अग्रवाल ने आमजन से अपील की कि नशीले पदार्थों से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना प्रशासन को दें। ऐसी सूचनाओं की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी तथा सूचना देने वाले को नियमानुसार प्रोत्साहनध्पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।

गिर्राज घाट पर स्वच्छता श्रमदान आयोजित

नवभारत न्यूज
श्योपुर 27 अप्रैल. कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत नगर पालिका श्योपुर के तत्वाधान में जनभागीदारी से सीप नदी के गिर्राज घाट पर स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के तहत गायत्री परिवार, जन अभियान परिषद, मातृछाया एवं प्रस्फुटन समिति के सदस्यों, नागरिको एवं नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से श्रमदान करते हुए गिर्राज घाट की साफ-सफाई का कार्य किया गया। इस अवसर पर सुजीत गर्ग, श्रीमती मिथलेश तोमर, कैलाश पाराशर, पार्षद प्रतिनिधि दीपचंद्र रेगर, चौथमल शर्मा, राजेन्द्र गुप्ता, जन अभियान परिषद की जिला समन्वयक श्रीमती नेहा सिंह, भास्कर टकसाली, सत्यभानु जाटव, सुधाकर पचौरी, अरविन्द पाराशर, ओमप्रकाश गुप्ता, राजेश मीणा, कृष्णगोपाल शर्मा सहित अन्य नागरिक उपस्थित रहे, इस अवसर पर जल संरक्षण की शपथ भी ली गई।